रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1966 (वैशाख 10, 1888)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1966 (VAISAKHA 10, 1888)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 19 अप्रैल 1966 तक प्रकाशित किये गये थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 19th April 1966 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
61	No. 45-ITC(PN)/66, dated 7th April, 1966.	Ministry of Commerce.	Imports from the U.S.A. under U.S. AID Non-Project Loan, 1966.
	No. 46-ITC(PN)/66, dated 7th April, 1966.	Do.	Import entitlement against exports of Tea and Coffee.
	No. 47-ITC(PN)/66, dated 7th April, 1966.	Do.	Import of Components, raw materials and spares etc. from the U.S. under U.S. AID Non-Project Loan, 1966.
62	No. 3-ITC(PN)/66, dated 7th April, 1966.	Do.	Export of Onion to Ceylon.
63	No. RSI/1/66-L., dated 14th April, 1966	Rajya Sabha Secretariat.	The President prorogues the Rajya Sabha.
	सं० आर० एस० 1/1/66-एल, दिनांक 14 अप्रैल 1966	राज्य सभा सचिवालय	राष्ट्रपति ने राज्य सभा का सत्रावसान किया ।
64	No. RSI/2/64-L., dated 15th April, 1966.	Rajya Sabha Secretariat.	The President summon the Rajya Sabha to meet on 3rd May 1966.
	सं० आर० एस० 1/2/66-एल, दिनांक 15 अप्रैल 1966	राज्य सभा सचिवालय	राष्ट्रपति ने राज्य सभा को समवेत होने के लिए 3 मई 1966 को आमन्त्रित किया ।
65	No. 48-ITC(PN)/66, dated 15th April, 1966.	Ministry of Commerce.	Import of pet Animals and Birds under the Baggage Rules.
	No. 49-ITC(PN)/66 dated, 16th April, 1966.	Do.	Import of machinery and equipments from USSR on 'deferred payment' terms.
66	No. 4-ETC (PN)/66. dated 16th April, 1966.	Do.	Export of Garments and Made up articles made from Cotton handloom commonly known fabrics as "Bleeding Madras".
67	No. CMW/1793, dated 18th April, 1966.	Cabinet Secretariat.	Inclusion of Dr. Vikram A. Sarabhai as a member of the National Defence Council.
68	No. 50-ITC(PN)/66, dated 19th April, 1966.	Ministry of Commerce.	Import of Components, Raw materials and spares from the U.S. under U.S. Aid non-Project Loan 1966.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची
(CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाएं ..	351
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	371
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ..	19
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं ..	251
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—

	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	781
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii) (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1207
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	123
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	277
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	159
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	47
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	281
भाग I—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	99
पूरक सं० 18—	
23 अप्रैल 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	607
3 अप्रैल 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	619

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	351
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	371
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	19
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	251
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	781
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1207
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ...	123
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	277
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	159
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	47
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	281
PART IV—Advertisement and Notices by Private Individuals and Private Bodies	99
SUPPLEMENT No. 18—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 23rd April 1966	607
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 3rd April 1966	619

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनाक 18 अप्रैल 1966

सं० 34-प्रेज/66—राष्ट्रपति, प्रादेशिक सेना के निम्नांकित आयुक्त अधिकारियो को सराहनीय सेवा के लिए 'प्रादेशिक सेना अलंकरण' प्रदान करते हैं :—

मेजर अमलेन्द्र लाल कार (टी० ए०—40121),
इन्फैन्ट्री (कार्यनिवृत्त)।

मेजर राजा पानगंटि वेंकैटराम रायनिंगार (टी०ए०—40131)
इन्फैन्ट्री (पद-त्याग)।

दिनाक 22 अप्रैल 1966

स० 35-प्रेज/66—राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नाकित अधिकारी को उसकी विशिष्ट सेवाओ के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं —

श्री चम्पकलाल हरिशंकर दवे,
पुलिस निरीक्षक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
गुजरात।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक से संबंधित नियमो के नियम 4 (ii) के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

सं० 36-प्रेज/66—राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारियो को उनकी सराहनीय सेवाओ के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

श्री दिलावर सिंह दौलत सिंह रायज़ादा,
पुलिस निरीक्षक,
गुजरात।

श्री गोपी मोहने सान्याल,
मुख्य वेतार-प्रचालक,
गुजरात।

2. ये पदक पुलिस पदक से संबधित नियमो के नियम 4(ii) के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं।

वाई० डी० गण्डेविया, राष्ट्रपति के सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनाक 19 अप्रैल 1966

संकल्प

कृषि संबंधी पैनल का पुनर्गठन

स० 5-24/65-कृषि—कृषि सम्बन्धी पैनल मे कृषि, ग्रामीण विकास और सहकार में प्रमुख अनुभवी गैर-सरकारी व्यक्तियो, तथा कृषि विकास से सम्बन्धित व्यापक प्रश्नो यानी स्थानीय कृषि दशाओं एवं हितो का ज्ञान रखने वाले किसानो को रखा गया था। इस पैनल का गठन तीसरी पचवर्षीय योजना के लिए कृषि कार्यक्रम तैयार करने में आयोग को सहायता प्रदान करने के लिए योजना आयोग के दिनाक 7 सितम्बर 1959 के सकल्प संख्या 20(3)/59-कृषि तथा दिनाक 21 सितम्बर 1962 के संकल्प सख्या 20-4/62-कृषि में किया गया था।

2. कृषि कार्यक्रमों का विभिन्न क्षेत्रो मे कार्यान्वयन, चौथी पंचवर्षीय योजना में इनकी प्रगति का पर्यवेक्षण और पैनल में उन अनुभवी व्यक्तियो को शामिल करने के लिए जिन्होने पिछले पैनल के गठन के बाद कृषि के विभिन्न क्षेत्रो में प्रमुखता प्राप्त कर ली है और कृषि विकास से सम्बन्धित विभागों से सम्बद्ध सरकारी अधिकारियो को शामिल करने के लिए पैनल से सलाह लेनी आवश्यक है, अतः योजना आयोग ने पैनल के पुनर्गठन करने का निर्णय किया है।

3 पुनर्गठित पैनल निम्न प्रकार से होगा —

अध्यक्ष

प्रोफेसर वी० के० आर० वी० राव,
सदस्य, योजना आयोग।

सदस्य

1. श्री रघोत्तम रेड्डी
2. श्री दिनेश प्रसाद सिंह
3. श्री दयालजी भाई गोविन्दजी पटेल
4. श्री डी० एस० साहनी
5. श्री आर० पी० स्वयम्भागौंडर
6. श्री ऋषभ कुमार
7. श्री हरिश्चन्द्र जी पटेल
8. श्री के० एम० वेंगूचेट्टियर
9. श्री डी० टी० नगेश
10. श्री कपिलेश्वर प्रसाद नन्दा
11. श्री अर्जुन सिंह
12. श्री भानुप्रताप सिंह
13. श्री शिवराज सिंह
14. श्री नृसिंह जी मुकर्जी
15. श्री मनोहर दास सिरकेक
16. श्री अनन्देश्वर बरुआ
17. सरदार डी० के० जाधव
18. हरिकृष्ण मेहताब, संसद्-सदस्य
19. श्री विभूति मिश्र, संसद्-सदस्य
20. श्री एस० एन० द्विवेदी, ससद्-सदस्य
21. श्री आर० वी० रेड्डियर, संसद्-सदस्य
22. श्री पी० एस० पाटिल, ससद्-सदस्य
23. श्री एम० दास गुप्त, ससद्-सदस्य
24. उपाध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् **पदेन**
25. अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक सम्बन्धी पैनल **पदेन**

26. अध्यक्ष, कृषि प्रशासन सम्बन्धी विशेषज्ञों का पैनल — पदेन
27. अध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्रियों का पैनल — पदेन
28. अध्यक्ष, गोसंवर्द्धन की केन्द्रीय परिषद् — पदेन
29. प्रो० डी० आर० गाडगिल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकार संघ और सदस्य, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम
30. एम० आर० सिंडे, डिप्टी गवर्नर, रिज़र्व बैंक आफ इंडिया — पदेन
31. अध्यक्ष, भारत का खाद्य निगम — पदेन
32. अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग — पदेन
33. श्री वी० कूरियन, डेयरी विकास बोर्ड
34. डा० पी० एस० लोकनाथन, महानिदेशक, व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्
35. डा० ए० एम० खुसरो, आर्थिक विकास संस्थान
36. श्री के० संथानम, पंचायतीराज की राष्ट्रीय परिषद्
37. डा० जे० एस० पटेल
38. श्री एम० वाई घोरपडे
39. श्री टी० एस० कृष्णन
— सदस्य, राष्ट्रीय आयोजन परिषद्
40. सचिव, योजना आयोग — पदेन
41. सचिव, कृषि विभाग — पदेन
42. सचिव, खाद्य विभाग — पदेन
43. सचिव, सामुदायिक विकास विभाग — पदेन
44. सचिव, सहकार विभाग — पदेन
45. सचिव, सिंचाई व बिजली मंत्रालय — पदेन
46. सचिव, उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय — पदेन
47. सचिव, पैट्रोलियम और रासायनिक मंत्रालय — पदेन
48. कृषि उत्पादन आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश — पदेन
49. कृषि उत्पादन आयुक्त, असम — पदेन
50. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार — पदेन
51. कृषि उत्पादन आयुक्त, गुजरात — पदेन
52. कृषि उत्पादन आयुक्त, जम्मू तथा कश्मीर — पदेन
53. कृषि उत्पादन आयुक्त, केरल — पदेन
54. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश — पदेन
55. कृषि उत्पादन आयुक्त, महाराष्ट्र — पदेन
56. कृषि उत्पादन आयुक्त, मद्रास — पदेन
57. कृषि उत्पादन आयुक्त, मैसूर — पदेन
58. कृषि उत्पादन आयुक्त, उड़ीसा — पदेन
59. कृषि उत्पादन आयुक्त, पंजाब — पदेन
60. कृषि उत्पादन आयुक्त, राजस्थान — पदेन
61. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश — पदेन
62. कृषि उत्पादन आयुक्त, पश्चिमी बंगाल — पदेन
63. कृषि उत्पादन आयुक्त, नागालैण्ड — पदेन
64. कृषि उत्पादन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश — पदेन

सदस्य-सचिव

65. संयुक्त सचिव (कृषि) योजना आयोग

पंजाब और नागालैण्ड राज्यों के प्रतिनिधि बाद में अधिसूचित किए जाएंगे ।

4. पैनल, विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए समितियां या दल गठित कर सकता है या सदस्यों को सहयोजित कर सकता है ।

5. पैनल या इसकी समितियां या दल की बैठकें आवश्यकतानुसार नई दिल्ली या अन्य स्थान पर हो सकती हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व-साधारण की सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जी० आर० कामत, सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1966

संशोधन

सं० 26(1)-टैरि/63—भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय के संकल्प सं० 26(1)-टैरि/63, दिनांक 19 फरवरी 1966, जो कि भारत के राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित हुआ था, के क्रमांक 7 पैरा 1 के आगे जो नाम तथा प्रविष्टि दी गई है उसमें संशोधन होकर उसके स्थान पर निम्न रख दिया जायगा :—

7. श्री एस० बनर्जी, उप-सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय, नई दिल्ली । — सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संशोधन सभी सम्बद्धों को भेज दिया जाय और सामान्य सूचना के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय ।

बी० कृष्णामूर्ति अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 1966

संकल्प

सं० एस० एस० आई० (ए०)-19(18)/65—भारत सरकार ने उद्योग तथा संभरण मंत्रालय (उद्योग विभाग) में 10 सितम्बर 1964 को डा० पी० एस० लोकनाथन, व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्, नई दिल्ली के महानिदेशक की अध्यक्षता में बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों को दुर्लभ कच्चे मालों के आवंटन और उनके उपयोग की जांच करने तथा सरकार से सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ।

2. समिति ने 28 मई 1965 को उद्योग तथा संभरण मंत्रालय (उद्योग विभाग) को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ।

3. समिति की सिफारिशें तथा उस पर किए गए सरकार के निर्णय अनुबन्ध में दिए गए हैं ।

4. सरकार समिति द्वारा किए गए बहुमूल्य कार्य की प्रशंसा करती है ।

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाए ।

यह आदेश भी दिया गया कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

ओंकारनाथ मिश्र, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

क्रम सं०	समिति की सिफारिशें	सरकार के निर्णय
(1)	(2)	(3)
1.	दुर्लभ कच्चे मालों का उनके क्षेत्र और वे किस एकक के हैं, इसका निर्देश किए बिना तथा उनके द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किए जाने वाले उत्पादनों की राष्ट्रीय प्राथमिकता को सम्पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए साम्यतः वितरण किया जाना चाहिए ।	स्वीकृत।कार्यान्वित किए जाने का आधार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होते ही इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया जाएगा । आंकड़े एकत्र करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना आरम्भ कर दिया गया है ।
2.	इस साम्यता का निश्चय करने के लिए इन एककों को बड़े (मध्यम को सम्मिलित कर) तथा लघु क्षेत्रों की वर्तमान परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए:— (1) एकक जो इस प्रकार की वस्तुएं/सेवाएं तैयार करते हैं जिनका उत्पादन केवल बड़े (मध्यम को सम्मिलित कर) क्षेत्र में ही किया जा सकता है । (2) एकक जो इस प्रकार की वस्तुएं/सेवाएं तैयार करते हैं जो, पैमाने की अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर कर, केवल बड़े (मध्यम को सम्मिलित कर) क्षेत्र अथवा लघु क्षेत्र में निर्मित की जा सकती है । (3) एकक जो लघु क्षेत्र में आते हैं किन्तु वे वस्तुएं/सेवाएं/पुर्जे/छोटे पुर्जे जोड़ कर या वे अन्य वस्तुयें तैयार करते हैं जो राष्ट्रीय हित में प्रमुख किस्म की होती हैं यद्यपि उनके बड़े (मध्यम को सम्मिलित कर) क्षेत्र में सापेक्ष एकक भले ही न हों । (4) लघु क्षेत्र में अन्य एकक । तकनीकी विकास के महा-निदेशालय तथा उद्योगों के राज्य निदेशकों के रजिस्टरों में जितने एकक दर्ज हैं उनका उपर्युक्त प्रकार से पुनवर्गीकरण किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक वर्ग के लिए समान आधार पर दुर्लभ कच्चे माल आवंटित किए जाने चाहिए ।	औद्योगिक एककों का अधिकांश अनुपात श्रेणी (2) में आएगा । श्रेणी (2) के एककों का दो शीर्षकों में वर्गीकरण किया जाएगा—(क) वे जो अनुसूचित एवं पंजीकृत क्षेत्र में आते हैं और (ख) वे जो लघु क्षेत्र में आते हैं । इस सिफारिश के आधार पर कच्चे माल का नियतन निर्धारित करने में स्थापित क्षमता तथा पिछले वर्षों में हुए उत्पादन दोनों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।
3.	दोनों क्षेत्रों में समान उद्योगों में से प्राथमिकताएं इस प्रकार रखी जानी चाहिए जिससे उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों का आवंटन अधिक हो तथा उन्हें अधिक आवश्यकता वाली वस्तुएं/सेवाएं उपलब्ध होंगी । निम्नलिखित वर्गों की सिफारिश की जाती है और उद्योग किसी एक अथवा उन वर्गों के किसी भी अन्य वर्ग के अन्तर्गत आना चाहिए । (1) प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताएं । (2) उद्योग जो कृषि एवं खाद्य उत्पादन के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है । (3) निर्यात अनुस्थापित उद्योग । (4) आयात प्रतिस्थापन उद्योग । (5) परिवहन और विद्युत् । (6) उद्योग जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रेलों और अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक पुर्जे इत्यादि बनाते हैं; वे एकक जो उन सहायक सामग्री, पुर्जों इत्यादि का उत्पादन करते हैं; जिनका आयात किया जाता है और जिनकी उपर्युक्त उद्योगों को चलाते रहने के लिए अनिवार्यतः आवश्यकता पड़ती है । (7) निर्माता की वस्तुएं तथा आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुएं बनाने वाले उद्योग । एकक जो किसी एक खास बड़े एकक के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें उसी सीमा तक, प्रधान एकक की प्राथमिकता मिलनी चाहिए । इन उद्योगों में विद्यमान क्षमता का और अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा विद्यमान उत्पादन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उन्हें यथासम्भव अतिरिक्त कच्चा माल प्राप्त कराया जाना चाहिए ।	स्वीकृत । "भेषज तथा औषधियों" को विशिष्ट रूप से श्रेणी (2) में बढ़ा दिया जाएगा ।
4.	संयुक्त समितियों को, जिसमें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय, तकनीकी विकास के महा-निदेशालय तथा केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उद्योग वर्गों की सम्पूर्ण आवश्यकता के आधार पर कच्चे माल आवंटित किए जाने चाहिए । लघु क्षेत्र में एक बार किसी विशेष उद्योग वर्ग की उपलब्धता निश्चित हो जाने पर	भारत सरकार इस सिफारिश के सिद्धान्त को स्वीकार करती है । इस्पात के संबंध में पहले ही इस्पात पूर्वता समिति बनी हुई है । सचिव (उद्योग) को इस समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा जिससे लघु क्षेत्र की समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा सके ।

(1)	(2)	(3)
	केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन को उनकी अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों में उनका पुनर्वितरण कराना चाहिए और राज्यों को उद्योग वर्गों की हकदारी सूचित करनी चाहिए जिससे विभिन्न राज्यों के उसी उद्योग वर्ग के भिन्न-भिन्न एककों में उनका समन्याय वितरण किया जा सके ।	अन्य कच्चे माल के संबंध में विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए प्रस्तावों की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें (1) सचिव, उद्योग मंत्रालय (2) सचिव, पूर्ति और तकनीकी विकास मंत्रालय, (3) सचिव, योजना आयोग और (4) कच्चे माल से संबंधित प्रशासनिक सचिव/समिति तकनीकी विकास का महा निदेशालय और विकास आयुक्त, लघु उद्योग से यथावश्यक परामर्श करेगी ।
5.	देशी दुर्लभ कच्चे मालों जैसे इस्पात, अल्युमिनियम, मूलभूत कार्बनिक रसायन और मध्यवर्ती पदार्थ, जिसमें रंगने के पदार्थ, मूलभूत अकार्बनिक रसायन जैसे कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, टिटेनियम डाइ-आक्साइड इत्यादि सम्मिलित हैं, भेषज, औषधियां, प्लास्टिक, संश्लिष्ट एवं प्राकृतिक रबड़ इत्यादि के संबंध में लघु एककों के लिए युक्तियुक्त मूल्यों पर एक न्यायोचित अंश अलग रख दिया जाना चाहिए ।	स्वीकृत/सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।
6.	विभिन्न लघु उद्योग संबंधी विश्वसनीय समान आंकड़े कुछ समय से उपलब्ध नहीं हैं । इस क्षेत्र की यह मूलभूत कमी यथाशीघ्र ठीक की जानी चाहिए । समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का आधार निश्चित करने के लिए राज्यों में लगभग 18 मास के समय में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हो जाने चाहिए यदि सभी राज्यों में इन आंकड़ों का संकलन समान आधार पर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं ।	यह सिफारिश स्वीकार की जाती है । राज्य सरकारों से आंकड़े एकत्र करने के लिए कहा जा रहा है । यह कार्य को उच्च पूर्वता के आधार पर किया जाएगा ।
7.	प्रत्येक राज्य में उद्योगों के राज्य निदेशकों को लघु क्षेत्र में वर्ग (2) और वर्ग (3) के सभी उद्योगों की (जिसका उल्लेख उपर्युक्त क्रम सं० 2 में किया गया है) उत्पादन क्षमता के अनुमान तथा विभिन्न दुर्लभ कच्चे माल के पिछले उत्पादन एवं आवश्यकता का अनुमान तैयार करना चाहिए और इसका समन्वय एवं समेकन कार्य केन्द्र में केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा किया जाना चाहिए । बड़े (मध्यम को सम्मिलित कर) क्षेत्र में तकनीकी विकास के महा-निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक निदेशालय के लिए वर्ग (1) और वर्ग (2) के उद्योगों की दुर्लभ कच्चे माल की आवश्यकता का अनुमान तैयार किया जाना चाहिए । अनुमानित आवश्यकताओं की इन दो सूचियों पर तत्पश्चात् केन्द्र के आवंटन अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए ।	स्वीकृत ।
8.	श्रेणी (4) के बहुत से एकक अन्य तीन वर्गों में सम्मिलित किए जाने के योग्य नहीं हैं । फिर भी इस वर्ग की रोजगार दिलाने की क्षमता काफी है और यह वर्ग कुशल कारीगरों, टेकनीशियनों एवं उद्यमियों के लिए प्रारम्भिक कार्य करता है जिससे उनके नए विचारों का पता लग सके और वे लघु क्षेत्र में वर्ग (3) या वर्ग (2) में स्नातक बन सकें । इस प्रकार के उद्यमियों के प्रवेश को सीमित कर देने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बड़ी हानि पहुंचेगी, जो पटुता और नवीन प्रक्रिया के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था करते हैं तथा कच्चे माल की अपनी अल्प आवश्यकता से अनुपात से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं । इस प्रकार की नई फर्मों के प्रवेश का, जिन्हें दुर्लभ कच्चे माल की आवश्यकता होती है, पथ-प्रदर्शन करना आवश्यक है जिससे स्वल्प विदेशी मुद्रा के साधन पर और अधिक भार न पड़े । किन्तु फिर भी क्षेत्र में दीर्घ-कालिक कार्यक्रम के रूप में नए प्रविष्ट करने वालों के लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए । सुझाव दिया गया है कि उपलब्धता पर निर्भर रहकर और अवशिष्ट उपाय के रूप में एवं आयात किए गए सभी दुर्लभ कच्चे मालों जैसे पुर्जों/फाल्तू हिस्सों, अलौह धातुओं और इस्पात के लिए प्रति छमाही कुछ थोड़ी सी राशि का तदर्थ आवंटन करने की अनुमति दी जानी चाहिए । केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन को उद्योगों के राज्य निदेशकों का इस दिशा में मार्ग-दर्शन करना चाहिए कि इस श्रेणी के अधीन किस प्रकार के उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सकता है । उद्योगों के निदेशक इन आवंटनों के लिए प्रायोजनाकारी अधिकारी होने चाहिए । इन प्रवेश करने वालों को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि उनका आवंटन उनके द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किए गए उत्पादन की उपलब्धता और पूर्वता पर निर्भर करेगा । इन एककों द्वारा उनकी तकनीकी सम्भाव्यता	भारत सरकार इस सिफारिश के सिद्धान्त को स्वीकार करती है ।

(1)	(2)	(3)
	और अर्थ-क्षमता सिद्ध हो जाने के पश्चात् उन्हें वर्ग (2) या वर्ग (3) में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए जिससे नए प्रवेश करने वालों को पुनः अवसर मिल सके ।	
9.	दोनों क्षेत्रों में विभिन्न एककों की क्षमता का उपयुक्त निर्धारण करना अनिवार्य है । इसका भी सुनिश्चय करना चाहिए कि इस प्रकार का निर्धारण समान आधार पर किया गया है । अतः सिफारिश की जाती है कि इस प्रयोजन के लिए कच्चे माल के संबंध में उपयुक्त सिद्धान्त तकनीकी विकास के महानिदेशालय, केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के पारस्परिक परामर्श निर्धारित किए जाने चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो वहां राज्य निदेशकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए । क्षमता का निर्धारण हो जाने से लघु क्षेत्र की क्षमता के संबंध में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी, जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए और उसे तकनीकी विकास के महा-निदेशालय, आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक तथा लाइसेंस देने वाली समिति के पास उनके इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाना चाहिए ।	क्षमता का निर्धारण करना एक जटिल समस्या है । क्षमता का निर्धारण करने के लिए एक युक्तिसंगत स्वीकृति प्रतिमानित कार्यविधि अपनाने के लिए कार्यवाही की जाएगी ।
10.	तकनीकी विकास के महा-निदेशालय, केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन व आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के प्रतिनिधियों की सम्मिलित नामिका को इस समय आयात किए जा रहे हिस्सों/पुर्जों की सूचियों की इस दृष्टिकोण से जांच करनी चाहिए कि क्या इनका निर्माण देश में ही किया जा सकता है । इन संयुक्त नामिकाओं को पूर्ति एवं निपटान महा-निदेशालयों के आयात की जांच भी करनी चाहिए जिससे देश के औद्योगिक एककों को अपना उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ।	स्वीकृत
11.	उद्योगों के राज्य निदेशक तकनीकी विकास के महा-निदेशालय की ओर से उनके निवेदन पर निरीक्षण कार्य कर रहे हैं । इस प्रक्रिया को जहां तक वांछनीय समझा जाए वहां तक बढ़ाया जाना चाहिए और वर्ष में कम से कम एक बार सभी एककों का निरीक्षण किया जाना चाहिए । निरीक्षण के ऐसे केन्द्रीय दलों के होने से निश्चित लाभ होगा, जिसमें विकास का महा-निदेशालय और केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित हों जो अकस्मात् कुछ बड़े और छोटे एककों का दौरा कर सकें।	इस सिफारिश का अन्तर्निहित सिद्धान्त एक स्वस्थ सिद्धान्त है । यद्यपि इस प्रकार के निरीक्षणों का आरम्भ किया जाएगा तो भी प्रत्येक एकक का वर्ष में एक बार निरीक्षण कर सकना तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि न की जाए । अतः प्रारम्भ में सिफारिश को यथासम्भव अमल में लाया जाएगा ।
12.	जहां तक सम्भव हो सके लघु उद्योगों को कच्चा माल राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा खोले गए कच्चे माल के डिपो के जरिए दिया जाना चाहिए । जिन राज्यों में इस प्रकार के निगम विद्यमान नहीं हैं उनमें तत्काल ही इनका निर्माण किया जाना चाहिए । कच्चे माल के ये डिपो सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जिससे लघु उद्योगपति को अपना कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सौ मील से अधिक यात्रा न करनी पड़े ।	स्वीकृत/राज्य सरकार से इस सिफारिश को कार्यान्वित करने तथा राज्य लघु उद्योग निगम/कच्चे माल डिपो की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा जाएगा ।
13.	कच्चे माल के डिपो को लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा नियंत्रित/पंजीबद्ध स्टाकिस्टों के रूप एवं खनिज और धातु व्यापार निगम/राज्य व्यापार निगम तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों द्वारा आयात किए गए कच्चे माल के वितरण के लिए एजेंट के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।	भारत सरकार यह सिफारिश स्वीकार करती है । यथासम्भव कार्यान्वित किए जाने के लिए इसे संबंधित संगठनों और राज्य सरकारों की जानकारी में लाया जाएगा ।
14.	जब प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों, रेलों, सरकारी उपक्रमों इत्यादि को उपलब्ध औद्योगिक कबाड़ बेचा जाता है तो उसका उपयुक्त अंश लघु एककों को, उस मूल्य पर, जो नीलाम मूल्य से कुछ संबंधित है, जहां कहीं भाव धाली प्रक्रिया लागू है, उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।	सरकार ने इस सिफारिश के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । यथासम्भव कार्यान्वित किए जाने के लिए इसे सरकारी उपक्रमों आदि की जानकारी में लाया जाएगा । इस प्रश्न को कि क्या लघु एककों को बेचे जाने वाले कबाड़ की नीलाम के मूल्य से अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को मूलतः जिस मूल्य पर प्राकृतिक धातु उपलब्ध कराई गई थी, से कोई संबंध होना चाहिए, अभी आगे जांच की जा रही है।
15.	दुर्लभ कच्चे मालों जैसे कास्टिक सोडा, पी०वी०सी० इत्यादि का राज्य कोटा लघु उद्योग निगमों को भी आवंटित किया जा सकता है । इस प्रकार के देशी मालों तथा उपर्युक्त क्रम सं० 14 में उल्लिखित औद्योगिक कबाड़ एकत्र करने और उसका वितरण करने में राज्य लघु उद्योग निगम का एक महत्वपूर्ण स्थान है ।	स्वीकृत/उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य सरकारों का ध्यान इस सिफारिश की ओर आकर्षित किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)
16.	राज्य निदेशालयों के प्रशासनिक, तकनीकी एवं सांख्यिकी सेक्शनों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है तथा निदेशालयों में उनके जिस स्थान की कल्पना की गई है उसे पूरा करने के लिए विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है। सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे संगठन के नमूने तथा वास्तव में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी इसका हिसाब लगा लें। इस संबंध में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) को राज्य निदेशालयों की सहायता करनी चाहिए।	स्वीकृत/उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य सरकारों का ध्यान इस सिफारिश की ओर आकर्षित किया जाएगा।
17.	समिति की सिफारिशों में केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के जिस स्थान की कल्पना की गई है, उसकी दृष्टि से केवल इसी कार्य के लिए तत्काल ही एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है। उसके लिए पर्याप्त सांख्यिकी तथा अन्य सहायता उपलब्ध करानी होगी।	सिफारिश नोट कर ली गई है और वह यथासम्भव कार्यान्वित की जाएगी।
18.	जब तक दीर्घ-कालिक सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की जाती, लघु क्षेत्र को पुर्जों, फाल्तू हिस्सों, अलौह धातुओं, इस्पात इत्यादि का आयात करने के लिए उन्हें जितनी कुल विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है उसमें वृद्धि करके इस क्षेत्र की, बड़े क्षेत्र के आवंटन में कटौती किए बिना, यदि संभव हो सके, अथवा अर्थ-व्यवस्था के किसी अन्य क्षेत्रों के आवंटनों में उपयुक्त समायोजन करके, अल्प-कालिक उपाय के रूप में आगामी तीन छमाहियों के लिए वर्तमान 17 करोड़ रु० की तात्कालिक सहायता बढ़ाकर 25 करोड़ रु० प्रति छमाही की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसकी जोरदार सिफारिश की जाती है कि यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 1965 की आवंटन अवधि से कार्यान्वित कर दी जानी चाहिए।	समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के पश्चात् विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति तेजी से खराब होते रहने तथा आपातकाल के कारण गिरती हुई स्थितिवश भारत सरकार के लिए यह सिफारिश स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं था। आपातकाल के कारण उत्पन्न स्थिति की सीमाओं के अन्दर रहते हुए लघु एककों के यथासम्भव हितों का ध्यान रखा जा रहा है।
19.	इस्पात प्राथमिकता समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों के लिए वर्तमान कार्यविधि यह है कि उसमें प्रत्येक निर्माण आर्डर के लिए अलग-अलग एकक को कितना परिमाण आवंटित किया गया है, इसका संकेत मिलना चाहिए। उद्योगों के राज्य निदेशकों को एककों से सम्पर्क स्थापित करने, उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करने, निर्माण के आर्डर नियत करने और मामलों को प्रस्तुत करने में काफी समय लगता है जिसका कारण यह होता है कि लघु एककों की संख्या अधिक होती है और प्रत्येक की अलग-अलग आवश्यकता कम होती है। इसका परिणाम यह होता है कि लघु क्षेत्र की स्थिति अलाभमय हो जाती है। सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक राज्य में राज्यों के लघु उद्योग निगमों/उद्योगों के राज्य निदेशकों द्वारा नाम-निर्देशित एजेंसी को राज्य में लघु एकक की ओर से प्रत्येक वर्ग के इस्पात उत्पादन के लिए एक ही निर्माण आर्डर खोलने की अनुमति दी जा सकती है। राज्य को नियत किया गया सम्पूर्ण परिमाण तत्पश्चात् प्राथमिकता के वर्ग में रखा जा सकता है। लघु उद्योग निगम आदेश को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय प्रबन्ध भी करेंगे तथा जिन-जिन लघु एककों को सामग्री आवंटित की जाती है उनसे अलग-अलग अपनी प्रतिपूर्ति कर लेंगे।	इस सिफारिश पर लोहा और इस्पात मंत्रालय तथा लोहा और इस्पात नियंत्रक के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1966

सं० 1-2/65-एम० ई० आई०—भूतपूर्व इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के संकल्प सं० 1-2/63-एम० ई० आई०, दिनांक 25 मार्च 1964 के संदर्भ में जिसमें बाल तथा रोलर बियरिंग उद्योग के लिए एक नामिका गठित करने का उल्लेख किया गया था।

2. निश्चय किया गया है कि श्री एम० रामाराव के स्थान पर, जो प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन चले गए हैं, श्री ए० एन० मुखर्जी, विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, तकनीकी विकास और पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली बाल तथा बियरिंग उद्योग की नामिका के सदस्य सचिव होंगे।

जे० एम० भटनागर, अवर सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 1966

सं० 14/3/65 सी०-5—भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के गठन के सम्बन्ध में, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के संकल्प सं०-6/25/63-ए०-10(सी०-5) दिनांक 20 नवम्बर, 1965 क्रमशः पैरा 3.1-क तथा 3.1-ख के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को 4 अप्रैल, 1966 से पांच वर्षों की अवधि के लिए उक्त आयोग के साधारण तथा संवादी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है :—

(क) साधारण सदस्य

(i) **संगठन के पैरा 3-I क (2) के अधीन**

अभिलेखागारों से सम्बन्धित शिक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव।

(ii) **संघटन के पैरा 3-I क (3) के अन्तर्गत**

1. प्रो० एम० मूजीब,
उप-कुलपति,
जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली-25,
2. प्रो० एन० आर० रे,
निदेशक,
इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज,
राष्ट्रपति निवास, **शिमला।**
3. डा० ताराचन्द,
एम० ए०, डी० फिल० एम० पी०,
8-नुगलक रोड, नई दिल्ली।

(iii) **संघटन के पैरा 3-I क (5) के अधीन**

1. आन्ध्र प्रदेश	.	श्री वी० के० बाबा, आई० ए० एस०, राज्य अभिलेखागारों के निदेशक, **हैदराबाद।**
2. आसाम	.	श्री पी० सी० शर्मा, कीपर आफ दी रिकार्ड्स, सचिवालय अभिलेख कार्यालय, **शिलांग।**
3. बिहार	.	डा० के० के० दत्त, अभिलेखागार-निदेशक, राजनीतिक विभाग, (राज्य अभिलेख कार्यालय) बिहार सरकार, **पटना।**
4. केरल	.	श्री पी० के० अब्दुल्ला, शिक्षा सचिव, अभिलेखागार के पदेन निदेशक, **त्रिवेन्द्रम।**
5. महाराष्ट्र	.	डा० एम० जी० दीक्षित, अभिलेखागार व ऐतिहासिक स्मारकों के निदेशक, महाराष्ट्र, एल्फिन्स्टन कालेज भवन, फस्टफ्लोर, **बम्बई-1।**
6. उड़ीसा	.	श्री एस० सी० डे०, अभिलेखागारों के सहायक निदेशक, राज्य अभिलेखागारों के प्रमुख, **भुवनेश्वर।**
7. पंजाब	.	श्री वी० एस० सूरी, अभिलेखागारों के निदेशक व क्यूरेटर राज्य संग्रहालय, **पटियाला।**
8. राजस्थान	.	श्री एन० आर० खड़गवाट, अभिलेखागार-निदेशक, **बीकानेर** (राजस्थान)।
9. पश्चिम बंगाल	.	श्री टी० के० मुखर्जी, एम० ए० डब्लू० बी० ई० एस०, अभिलेखागारों के सहायक निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, 6-भवानी दत्त लैन, **कलकत्ता-7।**

(iv) **संघटन के पैरा 3-I क (6) के अन्तर्गत**

1. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	.	प्रो० एस० नुरुल हसन, इतिहास विभाग के प्रोफेसर व प्रमुख, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, **अलीगढ़।**
2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय	.	प्रो० जे० पी० भटनागर, मध्ययुगीन व आधुनिक इतिहास विभाग के प्रमुख, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, **इलाहाबाद।**
3. आन्ध्र विश्वविद्यालय	.	प्रो० रामचन्द्रय्या, एम० ए० (आनर्स) पी० एच० डी०, बी० डी०, इतिहास विभाग के प्रोफेसर तथा प्रमुख, आन्ध्र विश्वविद्यालय, **वाल्टेयर।**
4. अन्नामलई विश्वविद्यालय	.	डा० बी० वी० रामानुजम, एम० ए० पी० एच० डी०, इतिहास व राजनीति विभाग के प्रोफेसर तथा प्रमुख, अन्नामलई विश्वविद्यालय, पोस्ट अन्नामलई नगर, (दक्षिण भारत)
5. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	.	डा० हीरालाल सिंह, इतिहास विभाग के प्रमुख, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, **वाराणसी-5।**
6. भागलपुर विश्वविद्यालय	.	डा० पंचानें मिश्र, इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग के प्रमुख, भागलपुर विश्वविद्यालय, **भागलपुर-7।**
7. बर्दमान विश्वविद्यालय	.	प्रो० एस० बी० चौधरी, एम० ए०, पी० एच० डी०, इतिहास तथा डीन आफ दा फैकल्टी आफ आर्ट्स विभाग के प्रमुख, बर्दमान विश्वविद्यालय, **बर्दमान।**
8. कलकत्ता विश्वविद्यालय	.	प्रो० एन० के० सिन्हा, एम० ए०, पी० एच० डी०, सिनेट हाऊस, कलकत्ता विश्वविद्यालय, **कलकत्ता।**
9. दिल्ली विश्वविद्यालय	.	प्रो० विशेश्वर प्रसाद, इतिहास विभाग के प्रमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय, **दिल्ली।**
10. गौहाटी विश्वविद्यालय	.	डा० एच० के० बरपुजारी, एम० ए०, पी० एच० डी०, इतिहास विभाग के प्रमुख, गौहाटी विश्वविद्यालय, **गौहाटी** (असम)
11. गुजरात विश्वविद्यालय	.	डा० एच० जी० शास्त्री, 'सुवास' आजाद सोसायटी, **अहमदाबाद-6।**
12. इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली।		डा० विमल प्रसाद, साउथ एशियन स्टडीज विभाग के प्रोफेसर तथा प्रमुख, इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, सप्रू हाउस, **नई दिल्ली-1।**
13. जबलपुर विश्वविद्यालय	.	डा० आर० एम० सिन्हा, एम० ए०, पी० एच० डी०, इतिहास अध्ययन विभाग के प्रमुख व प्रधानाचार्य महाकोशल आर्ट्स महाविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय, **जबलपुर।**
14. जादवपुर विश्वविद्यालय		डा० पी० सी० गुप्त, जादवपुर विश्वविद्यालय, **कलकत्ता।** (प्रो० डा० जे० एन० सरकार, इतिहास विभाग के स्थानापन्न प्रमुख 78/1, बड़े रायपुर रोड **कलकत्ता-32।**

	जुलाई, 1966 के प्रथम सप्ताह तक जादवपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे)।
15. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।	श्री मोहिब्बुल हसन, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के स्नातकोत्तर विभाग के प्रोफेसर तथा प्रमुख, जामिया कालेज, जामिया नगर, **नई दिल्ली-25**।
16. कर्नाटक विश्वविद्यालय	डा० ज० एस० दीक्षित, एम० ए०, पी० एच० डी०, इतिहास विभाग के प्रमुख, कर्नाटक विश्वविद्यालय, **धारवार** (मैसूर स्टेट)।
17. काशी विद्यापीठ	श्री भगवती प्रसाद पंथारी, इतिहास विभाग के प्रमुख, काशी विद्यापीठ, **वाराणसी-2**।
18. केरल विश्वविद्यालय	श्री पी० के० करुणाकर मेनन, एम० ए०, एम० लिट्, इतिहास के प्राध्यापक तथा भारतीय इतिहास की पत्रिका के सम्पादक, केरल विश्वविद्यालय, **त्रिवेन्द्रम्**।
19. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	श्री बी० एन० दत्त, एम० ए०, एम० लिट् (कन्टब) इतिहास के प्राध्यापक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, **कुरुक्षेत्र** (पंजाब)।
20. लखनऊ विश्वविद्यालय	डा० आर० एन० नागर, एम० ए०, पी० एच० डी०, मध्ययुगीन तथा आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, **लखनऊ**।
21. मगध विश्वविद्यालय	डा० आर० एन० प्रसाद, रीडर, इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, **बोध गया**।
22. महाराजा सयाजीराम विश्वविद्यालय	डा० एस० सी० मिश्र, फैकल्टी आफ आर्ट्स के इतिहास विभाग के प्रोफेसर तथा प्रमुख, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, **बड़ौदा-2**।
23. महाराठवादा विश्वविद्यालय	डा० आर० एस० गुप्त, प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति विभाग के प्रमुख, मराठवादा विश्वविद्यालय, **औरंगाबाद** (महाराष्ट्र)।
24. मैसूर विश्वविद्यालय	डा० बी० शेक अली, एम० ए०, पी० एच० डी० (अली०) पी० एच० डी० (लन्दन) इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग के प्रोफेसर तथा प्रमुख, मनासागनोत्री, **मैसूर-2**।
25. नागपुर विश्वविद्यालय	श्री बी० के० आप्टे, आधुनिक भारतीय इतिहास के प्राध्यापक (रीडर) नागपुर विश्वविद्यालय, **नागपुर**।
26. उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय	डा० डी० पी० सिन्हा, एम० ए० (लन्दन) पी० एच० डी० (लन्दन), इतिहास विभाग के प्रमुख, उत्तर बंगाल का विश्वविद्यालय, **सिलिगुरी**।
27. पूना विश्वविद्यालय	डा० आर० डी० भौकसे, नौरोजी वाडिया कालेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर इनचार्ज, पूना विश्वविद्यालय, **पूना-1**।
28. पंजाब विश्वविद्यालय	डा० आर० आर० सेठी, एम० ए०, पी० एच० डी०, इतिहास विभाग के प्रोफेसर तथा प्रमुख, पंजाब विश्वविद्यालय, **चंडीगढ़-3**।
29. पंजाब विश्वविद्यालय	डा० गंडा सिंह, एम० ए०, पी० एच० डी०, निदेशक, पंजाब ऐतिहासिक अध्ययन, पंजाबी विश्वविद्यालय, **पटियाला**।
30. राजस्थान विश्वविद्यालय	डा० सतीशचन्द्र, इतिहास के प्रोफेसर, इतिहास तथा भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, **जयपुर**।
31. रांची विश्वविद्यालय	डा० पी० एन० ओझा, इतिहास विभाग के प्रमुख, रांची विश्वविद्यालय, **रांची** (बिहार)।
32. सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात	डा० ए० आर० जी० तिवारी, इतिहास के स्थानकोत्तर विभाग के प्रमुख, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्लभ विद्यानगर (गुजरात)।
33. सागर विश्वविद्यालय	डा० एच० एल० गुप्त, एम० ए०, डी० फिल, इतिहास विभाग के प्रमुख, सागर विश्वविद्यालय, **सागर** (मध्य प्रदेश)।
34. शिवाजी विश्वविद्यालय	डा० ए० जी० पवार, एम० ए०, एल० एल० बी० (बम्ब०), पी० एच० डी० (लन्दन), बार-एट-ला, उपकुलपति, शिवाजी विश्वविद्यालय, **कोल्हापुर-3**।
35. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	डा० एम० रामाराव, इतिहास विभाग के प्रोफेसर तथा प्रमुख, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय कालेज, **तिरुपति** (आन्ध्र प्रदेश)।
36. विश्वभारती	डा० सुकुमार भट्टाचार्य, एम० ए० (कलकत्ता), पी० एच० डी० (लन्दन), इतिहास के प्रोफेसर, विश्वभारती, जि० वीरभूम (पश्चिम बंगाल)।

37. उत्कल विश्वविद्यालय ।	डा० एम० एन० दास, इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग के प्रोफेसर तथा प्रमुख, उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी-विहार **भुवनेश्वर**-4 ।

(V) संघटन के पैरा 3-I क (7) के अन्तर्गत

1. एशियाटिक सोसायटी, **बम्बई** ।	डी० जी० एम० मकेराइस, जेस, विल्ले, लाइब्रेरी सिनेमा के पास, न्यूक्वीन्स रोड, **बम्बई-1** ।
2. एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता ।	प्रो० एस० आई० सरस्वती, एम० ए०, एफ० ए० एस०, 6/ महिन्द्रा रोड, **कलकत्ता-25** ।
3. भारत इतिहास, संशोधक मंडल, पूना ।	प्रो० जी० एच० खरे, सचिव, भारत इतिहास संशोधक मंडल, 1321/सदा शिव पीठ, **पूना-2** ।
4. भारतीय विद्या भवन, बम्बई ।	डा० ए० के० माजूमदार, संयुक्त निदेशक (एकादमी) भारतीय विद्या भवन, हाउपट्टी रोड, **बम्बई-7** ।
5. विकास संस्थाओं का अध्ययन-केन्द्र, नई दिल्ली ।	डा० गोपाल कृष्ण, एम० ए० (ओक्सन), डी० फिल, (ओक्सन) संयुक्त निदेशक, विकास संस्थाओं का अध्ययन केन्द्र, 17-बी०-इन्द्र प्रस्थ मार्ग, **नई दिल्ली-1** ।
6. दकन कालेज, पोस्ट ग्रेजूएट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना ।	डा० ए० आर० कुलकर्णी, मराठा इतिहास के रीडर, दकन कालेज. **पूना-6** ।
7. भारतीय इतिहास तथा संस्कृति का हिरास अनुसंधान संस्थान, बम्बई ।	रेवरेण्ड (माननीय) एन्थोनी, डी कोस्ता एस० जे० सेन्ट जवियर्स कालेज, **बम्बई-1** ।
8. ऐतिहासिक प्रभाग विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली ।	श्री बी० के० बसु, निदेशक, ऐतिहासिक प्रभाग, पटियाला हाउस, अनेक्से-बी०-, नई दिल्ली ।
9. इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली ।	प्रो० पी० सी० चक्रवर्ती, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, **कलकत्ता-32** ।
10. भारतीय इतिहास कांग्रेस ।	डा० बी० पी० सक्सेना, अध्यक्ष, भारतीय इतिहास कांग्रेस, 32-हट्सन लाइन्स, **इलाहाबाद** ।
11. एतिहासिक अध्ययन की भारतीय संस्था, कलकता ।	डा० एस० पी० सेन, डी० फिल, डी० लिट०, निदेशक, एतिहासिक अध्ययनों की भारतीय संस्था, 5-ए०, मोती लाल नेहरू रोड, **कलकत्ता-29** ।
12. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इस्लामिक स्टडीज, नई दिल्ली	प्रो० एस० ए० अली, अवेतनिक सचिव, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इस्लामिक स्टडीज, पंचकुइया रोड, **नई दिल्ली-1** ।
13. भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्था, नई दिल्ली ।	निदेशक, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्था, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, रिंग रोड, **नई दिल्ली** ।
14. काशी प्रसाद जायस्वाल रिसर्च इन्स्टीटयूट, पटना ।	निदेशक, काशी प्रसाद जायस्वाल इन्स्टीटयूट, पटना ।
15. कर्नाटक ऐतिहासिक अनुसंधान सोसायटी धारवार	श्री नेमलूर रंगनाथ, एम० ए०, बी० टी०, एल० एल० बी०, एडवोकेट तथा इंडोलोजिस्ट, साधनाकेरीर, धारवार (मैसूर राज्य) ।
16. नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली ।	निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, दिल्ली ।
17. राजवाड़े संशोधन मंडल, धूलिया, (महाराष्ट्र) ।	श्री श्रीधर भास्कर भट्ट, बी० ए०, एल० एल० बी०, अवेतनिक सचिव, राजवाड़े संशोधन मण्डल, 4-लेन धूलिया (महाराष्ट्र) ।
18. सिख इतिहास अनुसंधान विभाग, खालसा कालेज, अमृतसर ।	प्रो० दिवान सिंह, एम० ए०, पंजाबी विभाग के **प्रमुख** खालसा कालेज, अमृतसर ।
19. विश्वेश्वरानन्द वैदिक अनुसंधान संस्थान, होशियारपुर ।	प्रधानाचार्य श्री रसी राम, एम० ए०, निदेशक, **सार्वजनिक प्रशासन** का भारतीय संस्थान, कालेज हाउस, उना (जिला होशियारपुर) ।

(ख)—संवादी सदस्य

संघटन के पैरा 3-I ख के अन्तर्गत

1. डा० अमलाश त्रिपाठी,
25 फ्लैट संख्या-25 बलाक सं०-, 3,
गवर्नमेंट हाउसिंग इस्टेट, गरीहाट रोड,
कलकत्ता-11 ।

2. डा० अम्बा प्रसाद,
एम० ए०, पी० एच० डी०,
इतिहास के प्राध्यापक,
दिल्ली विश्वविद्यालय, **दिल्ली-7** ।

3. डा० ए० एल० श्रीवास्तव,
एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिटे,
इतिहास के निवृत प्रोफेसर,
वजीरपुरा रोड, सिविल लाइंस, **आगरा-3** ।

4. डा० बी० बी० मिश्र,
एम० ए०, पी० एच० डी०,
द्वारा
सार्वजनिक प्रशासन की भारतीय संस्था,
रिंग रोड, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, **नई दिल्ली** ।

5. महामहोपाध्याय डी० बी० पोतदार,
4985-शानेवार पेठ,
महुपुरा **पूना-1** ।

6. डा० हरिराम गुप्त,
एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिट्,
इतिहास के रिटायर्ड प्रोफेसर,
पंजाब विश्वविद्यालय,
8/78 पंजाबी बाग, **दिल्ली**।

7. प्रो० एम० हबीब,
बदर बाग,
मुस्लिम यूनिवर्सिटी, **अलीगढ़**।

8. डा० एम० रथनास्वामी,
एम० पी०,
119, साउथ एवेन्यू, **नई दिल्ली-2**।

9. डा० पी० एम० जोशी,
एम० ए०, पी० एच० डी०,
डारा दकन कालेज, **पूना**।

10. डा० आर० सी० मजूमदार,
एम० ए०, पी० एच० डी०
बिनियनपाल रोड, **कलकत्ता-26**।

11. डा० रघुवीर सिंह,
एम० ए०, डी० लिट्०
रघुवीर निवास, सीता भाऊ (मध्य प्रदेश)।

12. डा० एम० गोपाल,
ऐतिहासिक प्रभाग,
विदेश मंत्रालय, **नई दिल्ली**।

13. डा० टी० रे चौधरी,
एम० ए०, पी० एच० डी०, डि० लिट०,
अर्थशास्त्र इतिहास के प्रोफेसर,
दिल्ली विश्वविद्यालय, **दिल्ली-7**।

टी० एस० कृष्णमूर्ति, उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th April 1966

No. 34-Pres./66.—The President is pleased to confer the "TERRITORIAL ARMY DECORATION" for meritorious service on the undermentioned commissioned officers of the Territorial Army :—

Major AMALENDRA LAL KAR (TA-40121),
Infantry (Retired).

Major RAJAH PANAGAMTI VENKATARAMA RAYANINGAR (TA-40131),
Infantry (Resigned).

The 22nd April 1966

No. 35-Pres./66.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for distinguished service to the undermentioned officer of the Gujarat Police :—

Shri Champaklal Harishankar Dave,
Inspector of Police,
Criminal Investigation Department,
Gujarat.

2. This award is made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of the President's Police and Fire Services Medal.

No. 36-Pres./66.—The President is pleased to award the Police Medal for meritorious service to the undermentioned officers of the Gujarat Police :—

Shri Dilawarsing Dolatsing Raizada,
Inspector of Police,
Gujarat.

Shri Gopi Mohine Sanyal,
Head Wireless Operator,
Gujarat.

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of the Police Medal.

Y. D. GUNDEVIA, Secy. to the President

PLANNING COMMISSION

RESOLUTION

New Delhi-1, the 19th April 1966

Reconstitution of the Panel on Agriculture

No. 5-24/65-Agri.—Whereas a Panel on Agriculture composed on leading non-officials with experience in agriculture, rural development and cooperation and farmers from different parts of the country with knowledge of local agricultural conditions and interest in broader questions relating to agricultural development was constituted under Planning Commission Resolution No. 20(3)/59-Agri. dated 7th September, 1959 and reconstituted in 1962, *vide* Resolution No. 20-4/62-Agri. dated 21st November, 1962 to assist the Commission in drawing up agricultural programmes for the Third Five Year Plan.

2. Whereas it is necessary to obtain the Panel's advice on implementation of the agricultural programmes in different fields, and reviewing their progress during the Fourth Five Year Plan and to include, in the Panel, other experienced persons, who have gained prominence in different fields of agriculture since the last Panel was constituted, and also officials connected with the Departments concerned with agricultural development, the Planning Commission have decided to re-constitute the Panel.

3. The Panel, as reconstituted, will consist of—

Chairman

Prof. V. K. R. V. Rao,
Member, Planning Commission.

Members

1. Shri Raghotham Reddy.
2. Shri Dinesh Prasad Singh
3. Shri Dayaljibhai Govindji Patel.
4. Shri D. S. Sawhney
5. Shri R. P. Swamyappa Gounder
6. Shri Rishabh Kumar
7. Shri Harishchandra G. Patil
8. Shri K. S. Vengu Chettiar.
9. Shri D. T. Nagesh
10. Shri Kapileshwar Prasad Nanda
11. Shri Arjun Singh
12. Shri Bhanu Pratap Singh
13. Shri Sheoraj Singh
14. Shri Nrisingha Mukerjee
15. Shri Manohar Dass Sirkek
16. Shri Anandeshwar Barua
17. Sardar D. K. Jadhav
18. Shri Harekrushna Mehtab, M.P.
19. Shri Bibhuti Mishra, M.P.
20. Shri S. N. Dwivedy, M.P.
21. Shri R. V. Reddiar, M.P.
22. Shri P. S. Patil, M.P.
23. Shri T. M. Das Gupta, M.P.
24. Vice-Chairman, Indian Council of Agricultural Research. ex-officio
25. Chairman, Panel on Agricultural Scientists. ex-officio
26. Chairman, Panel of Experts on Agricultural Administration. ex-officio
27. Chairman, Panel on Agricultural Economists. ex-officio
28. Chairman, Central Council of Gosamvardhana. ex-officio

29.	Prof. D.R. Gadgil	Chairman, National Cooperative Union and Member, National Cooperative Development Corporation.	
30.	Shri M. R. Bhide	Deputy Governor, Reserve Bank of India.	
31.		Chairman, Food Corporation of India	*ex-officio*
32.		Chairman, Agricultural Prices Commission.	,,
33.	Shri V. Kurian ...	Dairy Development Board.	
34.	Dr. P. S. Lokanathan	Director-General, National Council of Applied Economic Research.	
35.	Dr. A. M. Khusro	Institute of Economic Growth.	
36.	Shri K. Santhanam	National Council of Panchayati Raj	
37.	Dr. J. S. Patel ..	Members, National Planning Council.	
38.	Shri M. Y. Ghorpade		
39.	Shri T. S. Krishna		
40.		Secretary, Planning Commission.	*ex-officio*
41.		Secretary, Department of Agriculture.	,,
42.		Secretary, Department of Food.	,,
43.		Secretary, Department of Community Development.	,,
44.		Secretary, Department of Co-operation.	,,
45.		Secretary, Ministry of Irrigation & Power.	,,
46.		Secretary, Ministry of Industry and Supply	,,
47.		Secretary, Ministry of Petroleum & Chemicals.	,,
48.		Agricultural Production Commissioner, Andhra Pradesh.	,,
49.		Agricultural Production Commissioner, Assam.	,,
50.		Agricultural Production Commissioner, Bihar.	,,
51.		Agricultural Production Commissioner, Gujarat.	,,
52.		Agricultural Production Commissioner, Jammu & Kashmir.	,,
53.		Agricultural Production Commissioner, Kerala.	,,
54.		Agricultural Production Commissioner, Madhya Pradesh.	,,
55.		Agricultural Production Commissioner, Maharashtra.	,,
56.		Agricultural Production Commissioner, Madras.	,,
57.		Agricultural Production Commissioner, Mysore.	,,
58.		Agricultural Production Commissioner, Orissa.	,,
59.		Agricultural Production, Commissioner, Punjab.	,,
60.		Agricultural Production Commissioner, Rajasthan.	,,
61.		Agricultural Production Commissioner, Uttar Pradesh.	,,
62.		Agricultural Production Commissioner, West Bengal.	*ex-officio*
63.		Agricultural Production Commissioner, Nagaland.	,,
64.		Agricultural Production Commissioner, Himachal Pradesh.	,,
65.		Joint Secretary (Agriculture), Planning Commission.	*Member Secretary*
		Representatives of the States of Punjab and Nagaland will be notified later.	

4. The Panel may, for the study of different problems, constitute committees or groups and co-opt members.

5. The Panel or its committees or groups may meet at New Delhi or at such other place as may be necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. R. KAMAT, Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st April 1966

AMENDMENT

No. 26(1)-Tar/63.—In modification of Government of India, Ministry of Commerce Resolution No. 26(1)-Tar/63 dated the 19th February, 1966 published in Part I Section 1 of the Gazette of India, the name and entry appearing against S. No. 7 in paragraph 1 thereof shall be substituted as follows :—

7. Shri S. Banerjee, *Secretary.*
Deputy Secretary,
Ministry of Commerce,
New Delhi.

ORDER

ORDERED that the Amendment be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

B. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

New Delhi, the 12th April 1966

AMENDMENT

No. EEI-15(7)/65.—The following amendment is made in the Resolution constituting a Panel for Pumps and Compressors fans and blowers No. EEI-15(7)/65 dated the 4th March 1966 :

In serial No. 2 substitute :

'Shri R. V. Deshpande' *for* Shri P. V. Deshpande.

After serial No. 7 add :

'Persons representing other interests'.

After serial No. 10 add :

'Shri K. S. Prabhakar, *Member-Secretary*
Development Officer,
Directorate-General of
Technical Development.'

K. N. SHENOY, Dy. Secy.

New Delhi, the 19th April 1966

RESOLUTION

No. SSI(A)-19(18)/65.—The Government of India in the Ministry of Industry and Supply (Department of Industry) appointed on the 10th September 1964, a Committee under the Chairmanship of Dr. P. S. Lokanathan, Director General, National Council of Applied Economic Research, New Delhi, to examine the allotment and utilisation of scarce raw materials to the large, medium and small scale industries and make recommendations to Government.

2. The Committee submitted its Report to the Ministry of Industry and Supply (Department of Industry) on the 28th May 1965.

3. The recommendations of the Committee and the decisions of the Government thereon are set out in the Annexure.

4. Government wish to place on record their appreciation of the valuable work done by the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

O. N. MISRA, Jt. Secy.

ANNEXURE

S. No.	Recommendations of the Committee	Decisions of the Government
1	2	3
1.	The scarce raw materials should be equitably distributed without reference to the sector to which the units belong subject only to the overall national priorities of their end products.	Accepted. The recommendation will be implemented as soon as adequate data to form the basis for implementation, becomes available Necessary steps to collect the data have been taken in hand.
2.	For determining this equitability, these units should be divided into the following four broad categories on the basis of the present difinition of the large (including medium) and small scale sectors:— (*i*) Units producing such goods/services which could only be undertaken in the large (including medium) scale sector. (*ii*) Units producing goods/services which could manufacture, depending upon economies of scale, either in the large (including medium) sector or in the small scale sector. (*iii*) Units which fall in the small scale sector but produce goods/services/components/sub-assemblies or other items which are of a primary nature in the national interest, though they may not have comparable units in the large (including medium) scale sector. (*iv*) Other units in the small scale sector. All the units on the registers of the DGTD and State Directors of Industries should be be classified as above and scarce raw material allotted within each Group on a uniform basis.	By far the greatest proportion of the industrial units will fall in category (ii) The units in category (ii) will be classified under two heads (a) those in the sheduled and registered sector and (b) those in the small scale sector. In determining the allotment of raw materials on the basis of this recommendation, due account should be taken both of installed capacity and output during past years.
3.	Even amongst the comparable industries in the two sectors, priorities should be drawn up so that those industries with higher priority get higher allocations and provide the much more needed goods/services. The following categories are recommended and the industries must fall under one or the other of these categories. (1) Defence requirements. (2) Industries directly concerned with the development of agriculture and food production. (3) Export-oriented industries. (4) Import substitution industries. (5) Transport and power. (6) Units producing components, etc. required in certain vital sectors like railways and others; those producing accessories, components etc. which are imported and essentially required for keeping plant and machinery in the above industries running. (7) Producer goods and essential consumer goods industries. Units which are working as ancillaries to a particular large scale unit should get, to that extent, the priority of the principal unit. In these industries the existing capacities should be more fully utilized and additional raw material should be secured, to the extent possible to utilize existing production capacities.	Accepted. The item "Drugs & Medicines" will be added specifically in category (2).
4.	At the national level, joint committees, including representatives of the concerned administrative Ministry, DGTD and CSIO should allocate raw materials on the basis of overall requirements and availability to different industry groups. Once the availability to the particular industry group in the small scale sector is decided, the CSIO should redistribute it to the States in accordance with their estimated requirements and should also inform the States about the entitlement of the industry group so that there may be equitable distribution between the different units in the same industry group in different states.	The Govt. of India accept the principle of this recommendation. In respect of steel there is already the Steel Priority Committee. Secretary (Industry) will be included as a member of this Committee so that the problems of the small scale sector, could be adequately taken care of. In respect of other raw materials proposals worked out according to the existing procedure will be scrutinised by a Committee consisting of (1) Secretary, Ministry of Industry, (2) Secretary, Ministry of Supply & Technical Development (3) Secretary, Planning Commission and (4) Secretary, Administratively concerned with the raw material. The DGTD & the DGSSI will be consulted by the Committee where necessary.
5.	In regard to indigenous scarce raw materials such as steel, aluminium, basic organic chemicals and intermediates, including dyes, basic inorganic chemicals like caustic soda, soda ash, titanium dioxide, etc; pharmaceuticals and drugs, plastics, synthetic and natural rubber, etc., an equitable proportion should be set apart for the small scale units at reasonable prices.	Accepted. Steps will be taken to implement the recommendation.
6.	Dependable, uniform data regarding different small scale industries is not available over a period of time. This basic deficiency of the sector should be set right as quickly as possible, Adequate data to form the basis for implementation of the Committee's recommendations should be available in the States in about 18 months' time if immediate steps are taken to organise their collection and analysis on a uniform basis in all the States.	This recommendation is accepted. The State Governments are being requested to take section to collect data. This work will be taken on as a high priority item.
7.	For all category (ii) and category (iii) industries, (referred to in S. No. 2 above), in the small scale sector estimates of production capacities, past	Accepted.

1	2	3
	production and requirements of different items of scarce raw materials should be prepared in each State by the State Directorate of Industries and coordinated and consolidated at the Centre by the C.S.I.O. For all category (i) and category (ii) industries, in the large (including medium) scale sector estimates of scarce raw material requirements should be prepared by the D.G.T.D. for each Directorate for each of the categories. These two lists of estimated requirements should then be considered by the allocating authorities at the Centre.	
8.	A large number of units in category (iv) will not qualify for inclusion in the other three groups. The employment potential of this category is however, considerable and this category serves as the starting point for skilled workers, technicians and entrepreneurs to try out their new ideas and slowly graduate into category (iii) or category (ii) Industries in the small scale sector. It will be a serious disadvantage to the national economy to restrict the entry of such new entrepreneurs, who through ingenuity and innovation, provide goods and services and employment quite out of proportion to their meagre requirements of scarce raw materials. It is necessary to guide the entry of such new firms requiring scarce raw materials so that there may be no further strain on the meagre foreign exchange, resources. But even so provision should be made for new entrants into the sector as a long term programme. It is suggested that, depending upon availability and as a residual measure, an *ad-hoc* allocation of a small amount per half year for all imported scarce raw materials like components/spare parts, non-ferrous metals and steel might be allowed for this category. The C.S.I.O. should guide the State Directors of Industries as to the type of industries which could be fostered under this category. The Directors of Industries should be the sponsoring authorities for these allocations. It should be made clear to such entrants that allocations to them would depend on availability and the priority of their end-products. When these units prove their technical feasibility and viability, they should be transferred to either category (ii) or category (iii), giving scope for new entrants again.	The Government of India accept the principle of this recommendation.
9.	It is necessary to have proper assessment of capacities of different units in the two sectors. It is also to be ensured that such assessment is on a uniform basis. It is, therefore, recommended that suitable norms, in respect of raw materials, for the purpose be evolved by mutual consultation between the D.G.T.D. the C.S.I.O. and the State Directors be associated wherever necessary. The assessment of capacities will yield valuable information regarding capacities in the small scale sector, which should be analysed and passed on to the D.G.T.D. the C.C.I. & E. and the Licensing Committee for their use.	The assessment of capacities is a complex problem. Steps will be taken to secure a reasonably acceptable standard procedure for assessment of capacities.
10.	Joint panels of representatives of D.G.T.D. C.S.I.O. and C.C.I. & E. should scrutinize the lists of parts components now imported with a view to examine whether these could be produced within the country. These joint panels should also scrutinise the imports of the Directorate General of Supplies and Disposals with a view to encouraging industrial units in the country to take up their production.	Accepted.
11.	State Directors of Industries are doing inspection work on behalf of the D.G.T.D. at the latter's request. This practice should be extended to the extent desirable and there should be such inspection of all the units at least once a year. It would also be a definite advantage to have central teams of inspection consisting of representatives of D.G.T.D. and C.S.I.O. to visit a few large and small scale units at random.	The principle underlying this recommendation is a healthy one. While a beginning will be made with such inspections it will not be possible to inspect each unit once a year unless staff is greatly strengthened. To start with, therefore, the recommendation will be given effect to the extent possible.
12.	As far as possible scarce raw materials to small scale units should be channalised through raw materials depots opened by the State Small Industries Corporation. In States where such Corporations are not existing they should be constituted immediately. The raw material depots might be established at convenient places so that a small industrialist may not have to travel more than a hundred miles to secure his raw materials.	Accepted. The State Government will be requested to implement this recommendation and to take necessary steps to set up State Small Industries Corporation/ Raw Material Depots.
13.	The raw material depots should be recognised as controlled/registered stockists by the Iron & Steel Controller and as agents for distribution of imported material by the Minerals and Metals Trading Corporation/State Trading Corporation and such other organisations.	The Govt. of India accept this recommendation. It will be brought to the notice of the organisations concerned and the State Govts. for implementation.
14.	When industrial scrap available with defence establishments, railways, public undertakings etc. is disposed of an appropriate portion should be made available to the small scale units at a price which has some relation to the auctioned price, wherever the latter procedure is in force.	The principle of this recommendation has been accepted by the Govt. It will be brought to the notice of the public undertakings etc. for implementation to the greatest extent possible. The question whether the price of the scrap to be sold to the small scale units should have some relation to the auction price or to the price at which the virgin metal was originally made available to the public sector undertakings etc. is under further examination.
15.	States' quota of scarce materials like caustic soda, P.V.C. etc. might also be allotted to small Industries Corporations. In the pooling and distribution of such indigenous materials and	Accepted. Attention of the State Governments will be drawn to this recommendation for appropriate action.

1	2	3
	of industrial scrap referred to in S. No. 14 above, the State Small Industries Corporation have a useful part to play.	
16.	The administrative, technical and statistical sections in the State Directorates need reorganisation and considerable expansion to fulfill the role envisaged for the Directorates. The pattern of organisation and the actual strength required should be worked out immediately by all State Governments. The D.C.(SSI) should help the State Directorates in this regard.	Accepted. Attention of the State Governments will be drawn to this recommendation for appropriate action.
17.	In view of the role envisaged for the CSIO in the Committee's recommendations, it is necessary to post immediately a senior officer exclusively for this work. He will have to be supported by adequate statistical and other assistance.	The recommendation has been noted and will be implemented to the extent possible.
18.	Pending implementation of the long term recommendations, immediate relief should be provided to the small scale sector by increasing the total availability of foreign exchange for import of components, spare parts, non-ferrous metals, steel etc. to this sector from the present Rs. 17 crores to Rs. 25 crores per half-year for the next three half years as a short term measure, without cutting the allocations to the large scale sector, if possible, or by making suitable adjustments in the allocations to the other sectors of the economy. It is strongly recommended that this should be implemented with effect from the allotment period starting from 1st April, 1965.	Due to the rapid deterioration of the foreign exchange position since the Committee submitted its report and the worsening of the situation following the emergency, it was not possible for the Govt. of India to accept this recommendation. Within the limitations of the conditions imposed by the emergency, the interests of the Small Scale units are being taken care of to the greatest extent possible.
19.	The present procedure for submission of cases to the Steel Priority Committee requires indication of the individual works order for the quantity allotted to each unit. It takes a long time for the State Directors of Industries to contact the units, assess their requirements, allot works orders and put up the cases, in view of the small scale units being large in number and their individual requirements being small. This results in serious disadvantage to the small scale sector. It is recommended that the State Small Industries Corporations in each State/ the agency nominated by the State Directors of Industries might be permitted to open a single works order for each category of steel products on behalf of the small scale units in the State. The entire quantity allotted to the State might then be placed on the priority category. The Small Scale Industries Corporations will also make the financial arrangements for implementation of the order and get itself reimbursed from the individual small scale units, to whom the material is allotted.	This recommendation is under examination in consultation with the Ministry of Iron and Steel and the Iron & Steel Controller.

New Delhi, the 21st April 1966

No. 1-2/65-MEI.—Reference the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering Resolution No. 1-2/63-MEI, dated the 25th March, 1964 constituting a Panel for the Ball and Roller Bearing Industry.

2. It has been decided that Shri A. N. Mukherjee, Development Officer, Directorate General of Technical Development, Ministry of Technical Development and Supply, New Delhi, shall be the member Secretary of the Panel for the Ball and Roller Bearing Industry *vice* Shri M. Rama Rao, who has proceeded to U.K. for training.

J. S. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF IRON AND STEEL

RESOLUTION

New Delhi, the 20th April 1966

IRON AND STEEL ADVISORY COUNCIL

No. SC(I)-24(42)/65.—The Government of India have decided to reconstitute the Iron and Steel Advisory Council, which was set up in the late Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering Resolution No. SC(A)-24(116)/63 dated the 23rd March, 1964, as amended from time to time, to advise on all matters of a general character relating to iron and steel and in particular to problems pertaining to production, distribution, transport, research, import and export.

2. The composition of the Council will be as follows :

(i) *Chairman*—Minister of Iron and Steel.

(ii) Two *Ex-officio Members* :

(a) The President of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, or his nominee.

(b) The President of the Associated Chambers of Commerce of India, or his nominee.

(iii) Twenty-six members who are, in the opinion of the Government of India, capable of representing the interests of the producers, consumers, trade and mining and allied interests.

(iv) Eight representatives of the concerned Ministries of the Government of India.

(v) Secretary, Ministry of Iron and Steel.

(vi) Iron and Steel Controller—*Member-Secretary.*

3. The Chairman may also specially invite any other person or persons to represent the Iron and Steel Industry or trade or consumers to attend the meeting of the Council.

4. The Council will meet at least once a year.

The Council is constituted for a term of two years.

ORDER

ORDERED that this may be published in the Gazette of India for general information.

ORDER

The 20th March 1966

No. SC(I)-24(42)/65.—In terms of the Resolution No. SC(I)-24(42)/65, dated the 20th April, 1966, the Government of India hereby nominates the following persons to be members of the Iron and Steel Advisory Council :—

President, Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, Federation House, New Delhi or his nominee.

President, The Associated Chambers of Commerce of India, Royal Exchange, Calcutta-1, or his nominee.

Three representatives of Hindustan Steel Limited, Ranchi to be nominated by Hindustan Steel Limited.

One Representative of Bokaro Steel Limited, 1, Lower Circular Road, Calcutta-1.

Two Representatives of Tata Iron and Steel Company Ltd., 23-B, Netaji Subhas Road, Calcutta-1, to be nominated by Tata Iron and Steel Company.

Two Representatives of Indian Iron and Steel Company Limited, 12, Mission Row, Calcutta-1, to be nominated by Indian Iron and Steel Company.

Director and Vice-Chairman, Mysore Iron and Steel Limited, Bhadravati,(Mysore State).

Two Representatives of Steel Re-rolling Mills Association of India, 2, Brabourne Road, Calcutta, to be nominated by Steel Re-rolling Mills Association of India.

One Representative of the Indian Engineering Association, Royal Exchange, Calcutta-1, to be nominated by the Indian Engineering Association.

One Representative of the Indian Foundry Association, Stephen House, 4, Dalhousie Square East, Calcutta-1, to be nominated by the Indian Foundry Association.

Chairman, All India Manufacturers Association, Co-operative Insurance Building, Sir Phirozshah Mehta Road, Fort-Bombay-1.

One Representative of the Steel Exporters Association, 18, Rabindra Sarani, Calcutta-1, to be nominated by the Steel Exporters Association.

One Representative of the Joint Plant Committee, 18, Rabindra Sarani, Calcutta-1, to be nominated by the Joint Plant Committee.

One Representative of the Metal Scrap Trade Corporation Limited, 18, Rabindra Sarani, Calcutta-1, to be nominated by the Corporation.

One Representative of Minerals and Metals Trading Corporation, Express Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi, to be nominated by the Corporation.

One Representative of the All India Iron and Steel Merchants Federation, Loha Mandi, Motia Khan, New Delhi, to be nominated by the Federation.

One Representative of the Federation of Associations of Small Industries of India, 23-B/2, Rohtak Road, New Delhi, to be nominated by the Federation.

President, All India Iron & Steel Stockholders Federation, Ajmere ate, Delhi-6.

President, Iron, Steel and Hardware Merchants' and Manufacturers' Chamber of India, Steel Chambers, 153, Narayan Dhuru Street, Bombay-3.

Secretary, Joint Working Committee, (Indian Mining Association Etc.), No. 6, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

Shri C. R. Ramaswamy, M.L.A., Oriental Buildings Armenian Street, Madras-1.

Secretary, Ministry of Mines and Metals, New Delhi.

Secretary, Ministry of Supply & Technical Development, New Delhi.

Member (Transportation), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi

Additional Secretary, Ministry of Industry, New Delhi.

Chairman, Central Water and Power Commission, New Delhi.

Director General, Technical Development, New Delhi.

Financial Adviser, Ministry of Finance, (I. & S. Division), New Delhi.

Coal Mining Adviser, Ministry of Mines and Metals, New Delhi.

Other members to be hereafter specified by the Government of India to represent the Iron and Steel Industry or trade or consumers.

This is in supersession of Order No. SC(A)-24(116)/63, dated 23-3-1964 published in Part I, Section I of the Gazette of India, dated the 4th April, 1964 in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Iron and Steel).

P. P. CAPRIHAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

New Delhi, the 18th April 1966

No. F. 5(iv)-16/62-H.II/ME(PG).—It is hereby notified for general information that the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi which is a Statutory Body, is conducting under Section 24 of the All India Medical Sciences Act, 1956 (Act No. 25 of 1956) the undermentioned additional courses leading to the award of the following degrees and diplomas.

Degrees

1. M.Sc. in Biophysics.
2. M.D. in Ophthalmology.
3. D.M. in Pediatrics, Obstetrics and Gynaecology.
4. M. Ch. In Surgery and Orthopaedic Surgery.
5. M.H.A. in Hospital Administration.
6. B.Sc. (Hons.) in Anatomy, Physiology, Biochemistry, Biophysics, Pharmacology, Pathology and Microbiology.
7. M.Sc. in Nursing.
8. B.Sc. (Hons.) in Nursing.
9. M.Sc. in Drug Assay.
10. M. Ch. in Urology.

Diplomas

1. Diploma in Medical Laboratory Technique.
2. Diploma in Clinical Technology.
3. Diploma in Nursing Administration.
4. Diploma for Nursing Tutor.

2. It is notified for general information that in accordance with Section 23 of the All India Institute of Medical Sciences Act the medical degrees and diplomas granted by the Institute under the said Act shall be recognised medical qualifications for the purpose of Indian Medical Council Act, 1956 and shall be deemed to be included in the First Schedule to that Act.

K. M. L. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 14th April 1966

No. 2-2/65-FAME.—In the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture) Resolution No. 2-2/65-FAME dated 14-12-65 the composition of the National Campaign Committee and its Governing Board was announced but the names of non-official organisations and other non-officials were not specified. The President of the National Campaign Committee of the Freedom From Hunger Campaign is now pleased to decide that the representatives of the following non-governmental organisations and non-officials will be members of the National Campaign Committee and its Governing Board respectively until further orders :—

A. *NATIONAL CAMPAIGN COMMITTEE*

(a) 13 *non-governmental organisations concerned with rural development*

1. Bharat Krishak Samaj.
2. Bhartiya Grameen Mahila Sangh.
3. Young Farmers Association, India.
4. Bharat Sevak Samaj.
5. Bharat Yuvak Samaj.
6. All India Women's Conference.
7. Association of Voluntary agencies for rural development.
8. Sarva Seva Sangh
9. All India Panchayat Parishad.
10. Vaisali Sangh, Bihar.
11. National Agricultural Cooperative Marketing Federation Ltd.
12. Central Council of Gosamvardhana.
13. The National Cooperative Union of India.

(b) 6 *non-governmental organisations operating in urban areas*

1. All India Women's Food Council.
2. Central Social Welfare Board.
3. University Grants Commission.
4. Indian International Centre.
5. Indian Red Cross Society.
6. Indian Council of Child Welfare.

(c) 4 *industrial and commercial organisations*

1. Agricultural Sub-Committee of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
2. Fertiliser Association of India.
3. All India Agricultural Implements Organisation.
4. All India Manufacturers Organisation.

(d) 3 *press/information organisations*

1. All India Newspapers Editors Conference.
2. Delhi Union of Journalists.
3. Indian Council of World Affairs.

(e) 7 *individuals nominated in their personal capacity*

1. Dr. V. Kurien.
2. Dr. Shrimati Durgabai Deshmukh.
3. Shri J. Ragthotham Reddy.
4. Shri M. Gopalasami Thengondar.
5. Prof. V. M. Dandekar.
6. Shri S. B. Pandya.
7. Shri Bindeswari Prasad Singh.

GOVERNING BOARD

(a) 12 *non-governmental organisations concerned with rural development operating in rural areas*

1. Bharat Krishak Samaj.
2. Bhartiya Grameen Mahila Sangh.
3. Young Farmers Association.
4. Bharat Sevak Samaj.
5. Bharat Yuvak Samaj.
6. All India Women's Conference.
7. Association of Voluntary agencies for rural development.
8. Sarva Seva Sangh.
9. All India Panchayat Parishad.

10. Vaisali Sangh of Bihar.

11. National Agricultural Cooperative Marketing Federation Ltd.

12. Central Council of Gosamvardhana.

(b) *two non-governmental organisations operating in urban areas*

1. All India Women's Food Council.

2. Central Social Welfare Board.

(c) 3 *Industrial and commercial organisations*

1. Agricultural Sub-Committee of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

2. Fertilizer Association of India.

3. All India Agricultural Implements Organisation.

(d) 2 *Press organisations*

1. All India Newspapers Editors Conference.

2. Delhi Union of Journalists.

(e) *Individuals nominated in their personal capacity*

1. Dr. V. Kurien.

2. Dr. Shrimati Durgabai Deshmukh.

3. Shri J. Ragthotham Reddy.

4. Shri M. Gopalasami Thenondar.

5. Prof. V. M. Dandekar.

6. Shri S. B. Pandya.

7. Shri Bindeshwari Prasad Singh.

T. N. SARAF, Dy. Secy.

(I.C.A.R.)

RESOLUTIONS

New Delhi, the 16th April 1966

No. 6-1/65-*Reorgn*(*CC*).—The Second Joint Indo-American Team, appointed in 1959, to review the position of Agricultural Education, Research and Extension in India, recommended that in the interest of consolidating the Central Agricultural Research Programme and assuring adequate coordination, all Central Institutes and Commodity Committees should be brought under the full technical and administrative control of the Indian Council of Agricultural Research. This recommendation was strongly supported by the Agricultural Research Review Team, appointed in 1963. The Government of India have examined the above recommendations in the light of the actual functioning of the Central Commodity Committees during the past years and recently decided that the Commodity Committees should be abolished and the research work being conducted by them be integrated with the Indian Council of Agricultural Research, which should be suitably reorganised and strengthened, so as to enable it to develop and administer a National Programme of Agricultural Research, commensurate with the needs of the country. Accordingly, the Indian Central Oilseeds Committee was dissolved on 31st March, 1966 and its research activities have been assumed by the Indian Council of Agricultural Research, with effect from 1st April, 1966.

2. The Government of India have taken over the development and marketing functions handled by the Committee. In order to continue the association of the various official and non-official interests with the development of oilseeds and have the benefit of their continued advice, the Government of India have decided to constitute an Indian Oilseeds Development Council. To begin with, the Council will consist of the following :—

1. *Chairman*

Ch. Ram Dhan Singh,
Ex-Principal,
Punjab Agricultural College,
Opposite Civil Hospital,
Sonepat—District Rohtak (Punjab).

2. *Vice-Chairman*

The Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture.

3. *Members*

(a) *Representatives of the Central and State Governments*

(1) One representative each of the State Department of Agriculture to be nominated by the Governments of
(i) Gujarat.
(ii) Madras.
(iii) Uttar Pradesh.
(iv) Andhra Pradesh.
(v) Maharashtra.
(vi) Mysore.
(vii) Madhya Pradesh.

(2) One representative of the Planning Commission.

(3) One representative of the Ministry of Commerce.

(4) Agricultural Commissioner with the Government of India.

(b) *Growers representatives*

(1) Shri C. Putta Reddy, Ramalingapuram, *via* Pangal, Thottambedu P.O., Chittoor District (Andhra Pradesh).

(2) Shri K. Janardhan Reddy Shayampalli Village, Nagarkurnool Taluk, Mahaboobnagar District (Andhra Pradesh).

(3) Shri R. Venkatasubba Reddiar, M.P., Advocate, Tindivanam (South Arcot District—Madras). (144, North Avenue, New Delhi-1.)

(4) Shri M. K. Mathi Gowder, Mathipalyam, Coimbatore District.

(5) Shri G. R. Patil, B.A., LL.B., M.L.A., Sangli (Maharashtra).

(6) Shri D. M. Nikam, Bar-at-Law, M.L.A., Jalgaon (Maharashtra).

(7) Shri P. K. Desai, At & Post KIM, Taluka Olpad, District Surat (Gujarat).

(8) Shri D. N. Patel, C/o Shri Mohanlal Virjibhai Patel, Amreli, Gujarat.

(9) Shri Lakshmi Chandra Paliwal, Village Ingohta, District Hamirpur (Uttar Pradesh).

(10) Shri Mahendra Pal Singh, B.A. Village Jagdishpur, P.O. Bawan, District Hardoi.

(11) Shri Lakshman Singh, 9, Nehru Road, Meerut.

(12) Chaudhary Suresh Chandra, Secretary, M.P. Young Farmers' Association, Ghotagaon (District Narsingpur-M.P.).

(13) Shri M. C. Bondriya, Chief Editor "Krishak Jagat", Post Box No. 3, Bhopal (M.P.).

(14) Shri Sachchidanand Singh, Village & P.O. Bishrampur, Palamau District—Bihar.

(15) Shri Jatinder Mohan Majumdar, B.A., Vice-President, West Dinajpur District Farmers' Forum, P.O. HILLI, District West Dinajpur.

(16) Shri G. Shivappa, B.A., LL.B., 181, Palace Orchard Lower, Sadashivnagar (3), Bangalore-1. (Chittaldurg—Mysore State).

(17) Shri Ram Singh, Secretary Farmers' Forum Scheme, Jaipur.

(c) *Representatives of Trade and Industry*

(1) Shri N. P. Nopany, 178, Mahatama Gandhi Road, Calcutta-7.

(2) Smt. Pratima Bose, Chairman, West Bengal Khadi & Village Industries Board, 14, Prince Street, Calcutta-13.

(3) Shri Sirsappa Ijari, M.L.A., Member of Khadi Board, Haripanhalli, District Bellary (Andhra Pradesh).

(4) Swami Ramanand Tirth, Vice-Chairman, Maharashtra State Khadi & Village Industries Board, Begumpeth, Hyderabad.

(5) Dr. A. C. Chhatrapati, C/o The Vanaspati Manufacturers' Association of India, 5th Floor, India House, Fort Street, Bombay.

(6) Shri Maddi Sudarsanam, M/s. Sudarsanam Oil Mills, Kothapet, Guntur (Andhra Pradesh).

(7) Shri C. V. Mariwala, Kanmoor House, Fifth Floor, 281-87, Narsinatha Street, Bombay.

(8) Shri Ramdas Kilachand C/o M/s. Devchand Kilachand, 45-47, Appolo Street, Bombay.

(9) Shri G. V. Swaika, 18-B, Brabourne Road, Calcutta-1.

(10) Shri F. Moerner, East Asiatic Co. (India), Pvt. Ltd., Mercantile Bank Building, First Line Beach, Madras-1.

(11) Shri E. R. Mahajani, Laxmi Oil Mills, Akola (Maharashtra).

(12) Shri Tokarshi Lalji Kapadia, Hyderabad.

(13) Shri Vishan Swarup Aggarwal, President, Indian Produce Association, Calcutta.

(14) Shri Devji Rattansey, C/o M/s. Hirji Govindji and Co., 25, Chinch Bunder, Bombay.

(d) *Representatives of Parliament*

(1) Shri S. S. Deshmukh, M.P., Advocate, Hingoli (District Parbhani-Maharashtra). (152, North Avenue, New Delhi-1.)

(2) Shri Mansinh P. Patel, M.P., behind Baroda Bank, Panchsil, Mehsana (North Gujarat).
(180, South Avenue, New Delhi-1).

(3) Shri C. L. Narasimha Reddy, M.P., Tarigonda, *Via* Vayalpad, District Chittoor (Andhra Pradesh).
(115, Daryaganj, Delhi-6).

(4) Shri P. Venkata Subbiah, M.P., Senjamala P.O., *Via* Koilkuntala, Kurnool District (Andhra Pradesh).
(25, Canning Lane, New Delhi-1).

(e) *Others*

(1) Shri G. U. Rao, 54, Candappa Chetty Street, G.T. Madras-1.
(I.C.S. Road, Gudur.)

(2) Shri K. Subramanian Gounder, M.L.A., President, Co-operative Marketing Society, Tirachengode, Salem District (Madras).

(3) Shri T. V. Subba Rao, Principal Quality Control Officer, Tata Oil Mills Co., Bombay.

(f) *Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India, to represent interests not already represented in the Council.*

4. *Member-Secretary*

Deputy Secretary or any other officer dealing with the crop in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

5. *Observers*

(who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

(1) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture).

(2) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(3) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture).

(4) Chairman, State Trading Corporation.

(5) A representative of Railways.

(6) Director, Regional Office, Oilseeds Development, Hyderabad.

3. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider, from time to time, the Oilseeds Development Programmes formulated by the Central and State Governments;

(ii) to consider and review the progress of oilseeds development in the context of targets laid down;

(iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary;

(iv) to consider and review the problems of oilseeds marketing and trade, including price policy, and to make suggestions for improvement; and

(v) any other function, which may from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

4. The Council will meet periodically in important centres of trade and industry, in areas in which oilseeds are grown and will make its recommendations to the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. F. 6-9/65-Reorgn.(CC).—The Second Joint Indo-American Team, appointed in 1959, to review the position of Agricultural Education, Research and Extension in India, recommended that in the interest of consolidating the Central Agricultural Research Programme and assuring adequate coordination, all Central Institutes and Commodity Committees should be brought under the full technical and administrative control of the Indian Council of Agricultural Research. This recommendation was strongly supported by the Agricultural Research Review Team, appointed in 1963. The Government of India have examined the above recommendations in the light of the actual functioning of the Central Commodity Committees during the past years and recently decided that the Commodity Committees should be abolished and the research work being conducted by them be integrated with the Indian Council of Agricultural Research, which should be suitably reorganised and strengthened, so as to enable it to develop and administer a National Programme of Agricultural Research, commensurate with the needs of the country. Accordingly, the Indian Central Coconut Committee was dissolved on the 31st March, 1966 and its research activities (including the administrative control of the Coconut Research Stations) have been assumed by the Indian Council of Agricultural Research, with effect from the 1st April, 1966.

2. The Government of India have taken over the development and marketing functions handled by the Committee. In order to continue the association of the various official and non-official interests with the development of coconut and have the benefit of their continued advice, the Government of India have decided to constitute an Indian Coconut Development Council. To begin with, the Council will consist of the following :—

1. *Chairman*

Shri K. P. Madhavan Nair,
"Glen Brook", Ootacamund,
(Madras State).

2. *Vice-Chairman*

The Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture.

3. *Members*

(a) *Representatives of the Central and State Governments*

(1) One representative each of the State Department of Agriculture to be nominated by the Governments of
(i) Kerala,
(ii) Madras,
(iii) Mysore,
(iv) Andhra Pradesh,
(v) Orissa.

(2) One representative of the Planning Commission.

(3) One representative of the Ministry of Commerce.

(4) Agricultural Commissioner with the Government of India.

(b) *Growers' representatives*

(1) Shri C. A. Mathew, M.L.A., Thodupuzha, Kerala State.

(2) Shri V. O. Abraham, B.A., B.L., Advocate, Kottayam, Kerala State.

(3) Shri P. Ramachandran Nair, Porkalangad Farm, Kanipayoor, Kunnamkulam, Kerala State.

(4) Shri N. Narayana Kurup, Lakshmi Sadan, Champakulam, Alleppey District, Kerala State.

(5) Shri R. Srinivasa Iyer, Advocate, Pattukottai, Thanjavur District (Madras State).

(6) Shri N. Badrudeen, President, Coconut Growers' Association, Pamban Post, Ramanathapuram District (Madras State).

(7) Shri A. R. Subbiah Mudaliar, Idaikal P.O. *Via* Tenkasi, Tirunelveli District (Madras State).

(8) Shri V. Venkatappa, M.L.C., Landlord, Thittamaranahalli, Malur Hobli, Chennapatna Taluk, Bangalore District (Mysore State).

(9) Shri N. Ramabhadri Raju, Kodurupadu Post, Amalapuram, East Godavari (Andhra Pradesh).

(10) Shri Harishchandra G. Patil, Bordi, District Thana, Maharashtra State.

(11) Shri Sasanka Sekhar Manna, Headmaster, Multi Higher Secondary School, Village Multi, P.O. Damna, District 24-Parganas (West Bengal).

(12) Shri Bimal Krushna Misra, Markandeswar Sahi, Puri (Orissa).

(c) *Representatives of Trade and Industry*

(1) Shri A. R. Sulaiman Sait, President, Oil Millers and Merchants Association, Alleppey, Kerala State.

(2) Shri A. R. M. Chakrapani Reddiar, 10, Kandappa Chetty Street, Madras.

(3) Shri P. T. John, "Parijatham", Edappalli P.O., Ernakulam District, Kerala.

(4) Dr. N. C. B. Nath, Hindustan Lever Ltd., Ballard Estate, Bombay.

(5) Shri V. J. Joseph, C/o M/s. Pothen Joseph & Sons Ltd., Alleppey, Kerala.

(d) *Representatives of Parliament*

(1) Shri Mathew Maniyangadan, M.P., Kottayam, Kerala State.

(205, North Avenue, New Delhi-1.)

(2) Shri Sudhansu Bhushan Das, M.P., 30-B, Ananda Banerjee Lane, Bhowanipur, Calcutta-20.

(150 South Avenue, New Delhi-2.)

(e) *Others*

(1) Shri C. M. John, "Cherukara", Changanachery P.O., Kerala State.

(2) Shri P. B. Kurup, Techno Chemical Industries Ltd., Kozhikode, Kerala.

(f) *Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India, to represent interests not already represented in the Council.*

4. *Member-Secretary*

Deputy Secretary or any other Officer dealing with the crop in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture).

5. *Observers*

(who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

(1) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(2) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture).

(3) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(4) Chairman, State Trading Corporation.

(5) A representative of Railways.

(6) Director, Central Coconut Research Station, Kayangulam. (Kerala).

(7) Director, Central Coconut Research Station, Kasaragod. (Kerala).

(8) Director, Regional Office, Coconut Development, Ernakulam.

3. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider, from time to time, the Coconut Development Programmes formulated by the Central and State Governments;

(ii) to consider and review the progress of Coconut development in the context of targets laid down;

(iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary;

(iv) to consider and review the problems of coconut marketing and trade, including price policy, and to make suggestions for improvement; and

(v) any other function, which may, from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

4. The Council will meet periodically in important centres of trade and industry, in areas in which coconut is grown and will make its recommendations to the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. J. MAJUMDAR, Additional Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 21st April 1966

No. F.1-2/65-PE2.—In continuation of the Ministry of Education Notification of even number dated the 19th March, 1966,

Shri M. S. Sundara,
Joint Secretary,
Ministry of Finance,
New Delhi,

is nominated as a member of the All India Council of Sports with immediate effect and up to the 15th July, 1967, *vice* Shri K. N. Channa.

R. L. ANAND, Under Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Department of Transport, Shipping and Tourism)

(Transport Wing)

New Delhi, the 21st April 1966

No. SY-37(3)/66.—In this Ministry's notification No. SY-22(13)/60, dated 24th March 1964 para 3(i) may be amended to read as follows :—

3(i) The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism will be the President but the day to day functions of the Council will devolve on the Chairman.

No. SY-37(3)/66.—Para 3(ix) of this Ministry's notification No. SY-22(13)/60, dated 24th March 1964 as amended in subsequent Notification No. SY-22(13)/60, dated 28th October 1964, may now be read as follows :—

3(ix) Shri Govind H. Seth, Additional Director General of Shipping, Bombay—*Member-Secretary.*

GOPAL LAL MALHOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Works Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th April 1966

No. 25013(4)-EW/65.—In partial modification of late Ministry of Works & Housing Resolution No. 25013(4)-EW/65 dated the 20th/23rd November, 1965 the President has been pleased to decide that the Chief Engineer, Himachal Pradesh, may accept lowest tender or negotiated tender up to Rs. 25 lakhs without prior approval of the Himachal Pradesh Works Advisory Board.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

P. K. SEN, Dy. Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966